Amendment in Bonus Act to abolish the eligibility ceiling

993. SHRI GAYA SINGH:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether the workers in the Industries to which the payment of Bonus Act is applicable have been demanding to amend the present Act so as to abolish the eligibility ceiling for payment of Bonus; and

(b) if so, the details thereof and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) The Central Government have been receiving representations from trade unions for abolition and enhancement of the eligibility limit in the Payment of Bonus Act, 196S. The Act was last amended only in 199S raising the eligibility limit from Rs. 2500/- per month to Rs. 3500/- per month and calculation ceiling from Rs. 1600/- per month to Rs. 2900/- per month. Views of the State Governments and representatives of Employers and Workers are being invited.

Women entrepreneurs

994. DR. (SHRIMATI) BHARATI RAY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the industries, small/medium/large, having women entrepreneurs;

(b) the number of such women entrepreneurs in these industries;

(c) the ratio of women entrepreneurs in small scale industry to medium and large industry; and

(d) measures Government are taking to encourage women entrepreneurs in industry?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): Women entrepreneurs are represented in the small scale industries.

(b) There were 44,759 women Etrepreneurs in the small scale sector as per the Second All India Census of SSI units conducted with reference to year 1987-88.

नई निर्यात नीति के कारण व्यापार में हानि

995. श्री रामजीलाल: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई निर्यात नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस नीति के कारण व्यापार को भारी नुकसान हुआ है तथा गुजरात में अनेक फैक्ट्रियाँ बन्द हो गई; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार इस दोषपूर्ण निर्यात नीति को कब तक बदलेगी?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) 1 अप्रैल, 1992 से घोषित वर्तमान निर्यात और आयात नीति, 31 मार्च 1997 तक की अवधि के लिए वैध है। इस अवधि के दौरान एक स्थायी नीति ढांचे के अन्तर्गत मात्रात्मक प्रतिबन्धों और अन्य नियंत्रणों को दूर करने तथा निर्यात निष्पादन में सुधार लाने के उद्देश्य से नीति को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए नीति तथा प्रक्रियाओं का सफलतापूर्वक वार्षिक मूल्यांकन किया गया है।

(ख) निर्यात-आयात नीति के कारण गुजरात में फैक्ट्रियां बन्द होने की आज तक कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) निर्यात नीति तैयार करना एक सतत प्रक्रिया है जिसमें निर्यात संवर्धन परिषदों, व्यापार और उद्योग, संघों और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों से परामर्श किया जाता है तथा नीति में संशोधन करते समय, जनहित में जहां आवश्यक हो, इस संबंध में प्राप्त सभी सुझावों पर विचार किया जाता है।

State-wise foreign direct investment

996. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the foreign direct investment received. State-wise during the last five years;

(b) the details of sectors in which this foreign investment has been mads and